Public Finance
(लोक / सार्वजनिक वित्त)

- Budget
- Taxation

Budget
(बजट)

- बजट शब्द एक फ्रेंच शब्द "Bougette" से लिया गया है जिसका अर्थ होता है एक चमड़े का थैला।
- बजट एक वार्षिक वित्तीय विवरण है जो आने वाले वित्तीय वर्ष हेतु सरकार अपने अनुमानित व्यय एवं अनुमानित राजस्व को दर्शाती है।
- बजट एक आने वाले वित्तीय वर्ष हेतु सरकार के राजस्वों एवं व्ययों का एक Blue print है।

Budget

- केन्द्र सरकार ⇓ Art. 112
- राज्य सरकार ⇓ Art. 202

Process of Budget Making
बजट को बनाने की प्रक्रिया

① राजस्वों एवं व्ययों का आकलन

② बजटीय घाटों का आकलन

③ बजटीय घाटों को कम करना

④ बजट का प्रस्तुतीकरण एवं अनुमोदन

Process of Presentation & Approval of Budget
बजट की प्रस्तुतीकरण एवं अनुमोदन की प्रक्रिया

① बजट को प्रस्तुत करना

② आम चर्चा

③ विभागीय समितियों द्वारा जाँच

④ अनुदान माँगों पर मतदान
- → Policy Cut Motion (बजट की माँग घटाकर ₹1)
- → Economy Cut Motion (बजट की माँग विशिष्ट राशि से कम)
- → Token Cut Motion (बजट की माँग घटाकर ₹100 कम कर देना)

⑤ विनियोग विधेयक पारित करना (Art.-114)

⑥ वित्त विधेयक पारित करना (Art.-117)

Budget

⇓

Finance Minister

⇓

Department of Economic Affairs

→ Budget Division ⇓ Budget

→ Economic Division ⇓ Economic Survey

प्रत्येक वर्ष के बजट में सरकार तीन विभिन्न वर्षों के आँकड़ों को प्रस्तुत करती है। जैसे–

(a) वो वित्तीय वर्ष जो पूर्ण हो चुका है – Actual Estimates (AE)

(b) वो वित्तीय वर्ष जिसमें बजट पेश हो रहा है। – Budgetary Estimates (BE)

(c) एवं संशोधित अनुमान – Revised Estimates (RE)

(c) आने वाले वित्तीय वर्ष – Budgetary Estimates (BE)

2021-2022 ⇓ Actual Estimates वास्तविक अनुमान AE

2022-2023 → Budget Estimates; → Revised Estimates

2023-2024 ⇓ Budget Estimates (BE) ⇓ Budget

(2021-2022 and 2022-2023) → Economic Survey

Some historecal facts of Indian Budget
(भारतीय बजट के कुछ ऐतिहासिक तथ्य)

① भारत का प्रथम बजट ⟶ 7 Ap. 1860 - जेम्स विल्सन

② आजाद भारत का पहला बजट ⟶ 26 Nov. 1947
(R.K. शनमुखम चेट्टी)

③ गणतंत्र भारत का पहला बजट ⟶ 28 Feb. 1950
जॉन मथाई

④ 1950 तक बजट को राष्ट्रपति भवन में छापा जाता था लेकिन लीक होने के कारण इसे मिंटो रोड में छापने लगे। एवं 1980 में इसे स्थायी रूप से North Block (Finance Ministry) में छापने लगे।

- 1955-56 में सर्वप्रथम <u>बजट को हिन्दी में</u> छापा गया।

<u>बजट को तीन PM द्वारा प्रस्तुत किया गया है</u>।

(a) 1958-59 ⟶ पंडित जवाहरलाल नेहरू
(b) 1970-71 ⟶ Indira Gandhi
(c) 1987-88 ⟶ Rajeev Gandhi

- 1973-74 ⟶ Black Budget (by Y.V. Chavan)
(घाटा हुआ ₹550 Cr. का)

- <u>Morarji Desai ⟶ 10 times</u> (सर्वाधिक बार)

- पी० चिताम्बरम – 9 बार
प्रणब मुखर्जी – 8
यशवंत सिन्हा – 8
मनमोहन सिंह – 6

1992–93 → Liberalised Exchange Rate Management System
(उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली)
— By Manmohan Singh

1999 → बजट सुबह 11 बजे पेश होने लगा।
— यशवन्त सिन्हा (पहले शाम को 5 बजे)

1991–92 → E-pochal Budget (युगीन बजट)
↳ मनमोहन सिंह
↳ यह बजट नए आर्थिक नीतियों अर्थात उदारीकरण से संबंधित था।

1997–98 → Dream Budget
— पी० चिताम्बरम
(करों को घटाया गया)

2000–2001 → Melenium Budget
यशवंत सिंह
(IT क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन)

2017 में बजट में परिवर्तन

(a) रेल बजट आम बजट में शामिल हो गया।
(1924 में Accworth समिति के अनुसार Rail Budget को आम बजट से विभाजित कर दिया गया।

(b) बजट Feb. के प्रथम कार्य दिवस पर पेश होने लगा।
(पहले Feb. के अंतिम कार्य दिवस पर)

2019–2020 → निर्मला सितारमण ने बजट पेश किया
(यह भारत की दूसरी महिला तथा प्रथम
पूर्ण कार्यकालीन महिला वित्त मंत्री)

→ "Vahi Khata"

2020–2021 → longest बजटीय भाषण (2hr. 42 min.)
⇓
निर्मला सीतारमण

2021–2022 → प्रथम कागज-रहित बजट

Budget

सरकार के राजस्व (Govt. Revenues)

A↓ LT↑ ✗ — राजस्व प्राप्तियाँ (Revenue Receipts)

1. सभी प्रकार के कर
2. Fee, fines, लाइसेंस
3. उपहार एवं अनुदान
4. PSUs की आय
5. दिये गये ऋणों से प्राप्त ब्याज
6. राजगामी परिसंपत्तियाँ (Escheats) claim ✗
7. विशेष निर्धारण फीस
   - land में 4-lane
   - Airport.
   - Railway

A↓ LT↑ ✓ — पूँजीगत प्राप्तियाँ (Capital Receipts)

1. Borrowings (ऋण)
   - आंतरिक ऋण: RBI, Public
   - बाहरी ऋण: IMF, WB, Foreign Country
2. Disinvestment (विनिवेश)
3. Recovery of loans (लोन की वसूली)

सरकार के व्यय (Govt. Expenditure)

A↑ L↓ ✗ — राजस्व व्यय (Revenue Expenditure)

1. छात्रवृत्ति, वृद्धावस्था पेंशन, बेरोजगारी भत्ते
2. सब्सिडी
3. लिये हुए ऋणों का ब्याज भुगतान (केवल ब्याज L-constant)
4. laws & Order पर व्यय
5. अस्पतालों, विद्यालयों के कर्मचारियों का वेतन
6. राज्यों को अनुदान
7. सेना के लोगों पर व्यय

A↑ L↓ ✓ — पूँजीगत व्यय (Capital Expenditure)

1. सड़क, बाँध, पुल, स्कूल, अस्पताल के निर्माण पर व्यय
2. लिये हुए ऋणों को वापस करना

Government Revenues (सरकार के राजस्व)

- राजस्व प्राप्तियाँ Revenue Receipts
  - Tax-Revenue Receipt ①
  - Non-Tax Revenue Receipt ②-⑦
- पूँजीगत प्राप्तियाँ Capital Receipts
  - Debt Capital Receipt ①
  - Non-debt capital Receipt ②-③

Budget 2023 — 24

⇓

रूपया कहाँ से आता है?

① निगम कर (Corporate tax) → 15%
② आय कर (Income tax) → 15%
③ सीमा शुल्क (Custom duty) → 4%
④ केन्द्र उत्पादन शुल्क (Union Excise duty) → 7%
⑤ GST → 17%
⑥ गैर-कर प्राप्ति (Non-tax Receipts) → 6%
⑦ ऋण (Borrowing) → 34%
⑧ गैर ऋण पूँजी प्राप्तियाँ → 2%

NOTE ▷ सर्वाधिक राजस्व वाला कर → GST
राजस्व प्राप्तियाँ → 64%
पूँजीगत प्राप्तियाँ → 36%

रूपया कहाँ जाता है?

Budget 2023-24

1. ब्याज भुगतान (Interest Payment) → 20%
2. सेना (Defence) → 8%
3. सब्सिडी (Subsidy) → 7%
4. Pension → 4%
5. Central Sector Schemes → 17%
6. केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएँ → 9%
7. करों एवं शुल्कों में राज्यों का हिस्सा → 18%
8. वित्त आयोग और अन्य ट्रांसफर → 9%
9. अन्य व्यय → 8%

NOTE → (i) बजट 2023-24 में सर्वाधिक व्यय → ब्याज भुगतान (20%)

(ii) 2023-24 → कुल बजट → ₹45,03,097 Cr.

(iii) 2022-23 → कुल बजट → ₹ 39,44,909 Cr.

Types of Budgeting Techniques
बजट बनाने के तकनीकों के प्रकार

① Line-item based budgeting :—

जब सरकार आने वाले वित्तीय वर्ष के बजट को पूर्व वर्षों के आधार पर तैयार करती है।

② शून्य आधारित बजटिंग (zero based budgeting) :—

- सर्वप्रथम US में लाया गया।
- इसे पीटर पिर के द्वारा 1969 में दिया गया।
- भारत में इसे सर्वप्रथम 1983 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रयोग किया गया।
- भारत में इसे सर्वप्रथम राजीव गाँधी की सरकार ने 1986-87 के बजट में प्रयोग किया था
- इस प्रकार की बजटीय तकनीक में बजट को बिना किसी आधार के नए शिरे से निर्मित किया जाता है।
- इस प्रकार के बजट में बजट बनाते समय सभी खर्चों का मुल्यांकन नए सिरे से किया जाता है। एवं पूर्व वर्षों के बजट को नहीं देखा जाता है।

③ Gender-based budgeting :—

- इस प्रकार की बजटीय तकनीक में सरकार महिलाओं को सशक्त करने पर बल देते है। अर्थात जब सरकार लिंग असमानता को कम करने के दृष्टिकोण से बजट तैयार करती है।
- भारत में इसका प्रयोग बजट 2005-06 में किया गया था।
- विश्व में इसका प्रयोग सर्वप्रथम → Australia (1984)

④ परिणाम आधारित बजटिंग (Outcome based Budgeting):-

- इसे सूक्ष्म स्तरीय बजटिंग भी कहते हैं। — Micro
- जब सरकार अलग - अलग विभागों और मंत्रालयों के स्तर पर बजट बनाती है।
- इसे भारत में सर्वप्रथम 2005-06 में प्रयोग किया गया था।

इसका सत्यापन वित्त मंत्रालय एवं नीति आयोग द्वारा होता है।

⑤ प्रदर्शन आधारित बजटिंग (Performance-based budgeting)

- इसे वृहद / व्यष्टि स्तरीय (Macro level) बजट भी कहते हैं। अर्थात जो बजट वित्त मंत्रालय द्वारा संपूर्ण भारत के लिए बनाया जाता है।
- इसका सर्वप्रथम प्रयोग US ने कृषि क्षेत्र में 1949 में हूवर कमीशन की सिफारिशों द्वारा किया था।

~~• इसका~~ **NOTE!!** ➤

पहले भारत के बजट में खर्चों को विकास व्यय एवं गैर विकास व्यय के रूप में संदर्भित किया जाता था।

Sukhmay Chakravorty — 1985

- नियोजित व्यय (Planned Expⁿ)
- गैर नियोजित व्यय (Non-planned Expⁿ)

C. Rangrajan समिति - 2011

- राजस्व व्यय (Revenue Expenditure)
- पूँजीगत व्यय (Capital Expenditure)

• 2016 में भारत सरकार ने घोषणा की कि नियोजित एवं गैर नियोजित व्यय को खत्म करके राजस्व व्यय एवं पूँजीगत व्यय में वर्गीकृत किए जाएँगे एवं इसमें 2018 में लागू किया गया।
(2017-18)

नियोजित व्यय (Planned Expenditure)	गैर नियोजित व्यय (Non-planned Expenditure)
वह व्यय जो FYP पर आधारित होते हैं।	वह व्यय जो FYP पर आधारित नहीं होते हैं।
बिजली, पानी, प्रेषण, परिवहन, कृषि आदि पर व्यय।	रक्षा की सेवाओं पर व्यय, ब्याज भुगतान, प्रशासनिक सेवाओं, पेंशन, सब्सिडी आदि।

Types of Budget
(बजट के प्रकार)

- संतुलित बजट Balanced Budget ⇒ TE=TR
- घाटे का बजट Deficit Budget ⇒ TE>TR
- अधिशेष बजट Surplus Budget ⇒ TE<TR

Types of Budget Deficit
(बजटीय घाटे के प्रकार)

- राजस्व घाटा Revenue Deficit
- राजकोषीय घाटा Fiscal Deficit
- प्राथमिक घाटा Primary Deficit
- प्रभावी राजस्व घाटा Effective Revenue Deficit

राजस्व घाटा (Revenue Deficit) :–

राजस्व प्राप्तियाँ < राजस्व व्यय

राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit) :–

कुल व्यय > कुल राजस्व (ऋणों को छोड़कर

~~# प्राथमिक~~ कुल व्यय > राजस्व प्राप्तियाँ – गैर ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ

FD = TE – RR – NDCR

प्राथमिक घाटा (Primary Deficit) :–

राजकोषीय घाटा (ऋण) – ब्याज भुगतान

FD (borrowings) – Int. Payment

प्रभावी राजस्व घाटा (Effective Revenue Deficit) :–

2011 से (V. Chitambrambram)

राजस्व प्राप्तियाँ > राजस्व व्यय – GTS

राजस्व घाटा – GTS.

घाटे संबंधी आँकड़े (Deficit Statistics)

(केन्द्र बजट 2023-2024 के घाटे)

	2021-2022 Actual Estimates (AE)	2022-2023 Budget Estimate (BE)	2022-2023 Revised Estimate (RE)	2023-2024 Budget Estimate (BE)
राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit)	6.7	6.4	6.4	5.9
राजस्व घाटा (Revenue Deficit)	4.4	3.8	4.1	2.9
प्रभावी राजस्व घाटा (Effective Revenue Deficit)	3.3	2.6	2.9	1.7
प्राथमिक घाटा Primary Deficit	3.3	2.8	3.0	2.3

(बिहार बजट 2023-2024 के घाटे)

	2021-22 (Actuals)	2022-23 (BE)	2022-23 (RE)	2023-24 (BE)
Fiscal Deficit	3.8	3.5	8.8	3.0
Revenue Balance	-0.1	0.6	-3.6	0.5
(Primary Deficit)	1.7	1.3	6.7	0.8

Relationship between RD & FD
राजकोषीय घाटा एवं राजस्व घाटा संबंध

① **राजस्व घाटा > राजकोषीय घाटा**

तब राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए सरकार जो ऋण लेगी वह पूर्ण रूप से राजस्व घाटे को पूरा करने में प्रयोग होगा अर्थात लिया हुआ ऋण, गैर विकास व्यय पर खर्च होगा।

② **यदि राजकोषीय घाटा > राजस्व घाटा (FD > RD) :—**

तब सरकार द्वारा राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए लिया गया ऋण देश के उत्पादनशील कार्यों अर्थात पूँजीगत व्यय के लिये प्रयोग होगा।

③ **यदि राजस्व घाटा = 0**

तब सरकार के द्वारा लिए गये ऋण पूर्णतः देश के पूँजीगत व्यय पर लगेंगे।

Advantages & Disadvantages of Fiscal Deficit
राजकोषीय घाटे के लाभ एवं हानियाँ

राजकोषीय घाटे के लाभ :-

① व्यय अधिक होगा

② मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि होगी।

③ सार्वजनिक निवेशों में वृद्धि (Dams, पुल, सड़क आदि)

④ अधिक रोजगार के अवसर

राजकोषीय घाटे के नुकसान :-

① ऋण के जाल (यदि सरकार राजस्व घाटा को पूरा करने के लिए ऋण लेती है तब सरकार ऋण के जाल में फँसती चली जाती है।)

② मुद्रास्फीति दर में वृद्धि

③ भुगतान संतुलन में असंतुलन
(यदि कोई देश राजकोषीय घाटे में है तब उसे विदेशी देशों से ऋण लेना होता है एवं यह भुगतान संतुलन पर दबाव डालता है।

④ क्राउडिंग आउट of private investment
निजि निवेश को बाहर करना

यदि सरकार राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए अधिक से अधिक ऋण लेती है तब वित्तीय संस्थानों अर्थात बैंकों के पास निजि क्षेत्रों को ऋण देने के लिए कम मुद्रा होगी जिसके परिणामस्वरूप निजि क्षेत्रों को महँगी ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध होगा एवं जिससे निजि क्षेत्र कम ऋण लेंगे एवं अर्थव्यवस्था में कम निवेश करेंगे।

Tax to GDP Ratio
कर GDP अनुपात

$$\frac{Tax}{GDP} = \frac{10}{20} = 0.5 \; X$$

$$\frac{Tax}{GDP} = \frac{15}{20} = 0.75 \; ✓$$

वित्त वर्ष 2021–22 → कर GDP अनुपात = 11.4% (DT–6%, IT = 5.4%)

वित्त वर्ष 2022–23
- BE → 10.7%
- RE → 11.1%

वित्त वर्ष 2023–24 → 11.1% (DT = 6%, IT = 5.1%)

Fiscal Responsibility & Budget Management Act
FRBM Act – 2003

राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन

यह भारत में 2003 में पेश किया गया।

यह 5 Jul. 2004 से लागू हुआ।

FRBM के उद्देश्य :–

① राजकोषीय समेकन / राजकोषीय अनुशासन
(Fiscal consolidation)

② वृहद आर्थिक स्थिरता / व्यापक आर्थिक स्थिरता
(Macro Economic Stability)

③ राजकोषीय समेकन

④ मौद्रिक नीति एवं राजकोषीय नीति के बीच बेहतर समन्वय

FRBM Act

- **Old FRBM** (2004–09)
  ⇓
  विजय एल० कालेकर

  ① राजकोषीय घाटे को 2009 का 3% (प्रतिवर्ष 0.3% कम करना)

  ② राजस्व घाटे को शून्य करना (प्रतिवर्ष 0.5% कम करना)

- **New FRBM** (2016-17 – 2022-23)
  ⇓
  N.K सिंह

  ① 2022-23 तक राजकोषीय घाटे को 2.5% तक लाना (0.2% प्रतिवर्ष)

  ② राजस्व घाटे को 0.8% करना (0.5% प्रतिवर्ष घटाकर)

  ③ Debt to GDP Ratio को 60% (केन्द्र – 40% राज्य – 20%)

  ④ इसने सुझाव दिया कि एक 'राजकोषीय परिषद' होना चाहिए।

Fiscal Council

- जिसका कार्य केन्द्र एवं राज्य और मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति के बीच समन्वय करना होगा।

NK Singh :—

- इसने सुझाव दिया कि FRBM का नाम बदलकर "ऋण प्रबंधन एवं राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम एवं नियम" होना चाहिए।

Debt to GDP Ratio
ऋण GDP अनुपात

$$\text{Debt to GDP Ratio} = \frac{\text{ऋण}}{\text{GDP}}$$

वित्त वर्ष 2021 ⟶ 88.5%

वित्त वर्ष 2022 ⟶ 83.8%

वित्त वर्ष 2023 ⟶ 81%